

[2023] एस.सी.आर. 754

राज कुमार @ सुमन

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार

(आपराधिक अपील सं. 1471/2023)

11 मई, 2023

[न्या. अभय एस. ओका और न्या. राजेश बिंदल]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - एस.313-अभियुक्त की जाँच करने की शक्ति-कानून का सारांश।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - एस.313-का गैर-अनुपालन-अभियुक्त यू/एस से पूछताछ करते समय की गई चूक। 313, का प्रभाव-अपीलकर्ता को यू/एस. एस. के तहत दोषी ठहराया गया था।302, 307 आर/डब्ल्यू 120-बी, भा.दं.सं. सी. और तदनुसार सजा - हेल्ड: अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र कथित आपत्तिजनक परिस्थिति पीडब्लू5 के साक्ष्य में है, जिसने कहा कि अपीलकर्ता उस परिसर के बाहर अपने हाथ में एक कट्टा लेकर खड़ा था जहाँ अपराध हुआ था-हालाँकि, यह उसके बयान यू/एस में नहीं रखा गया था।313-इसलिए, उन्हें उक्त परिस्थिति की व्याख्या करने का कोई अवसर नहीं मिला जो उनकी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार था-इसलिए, उनके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को दूषित कर दिया गया-उच्च न्यायालय के विवादित

निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - एस.313 (5)-प्रासंगिक प्रश्न तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की सहायता का लाभ:बयान दर्ज करते समय यू/एस।313, अभियोजन पक्ष के गवाहों की बड़ी संख्या वाले मामलों में, न्यायिक अधिकारियों को एस का लाभ उठाने की सलाह दी गई। 313 (5) जो यह सुनिश्चित करेगा कि त्रुटियों और चूक करने की संभावनाओं को कम किया जाए-हालाँकि, इस प्रावधान पर बहुत कम ध्यान दे जाता है-राष्ट्रीय और राज्य न्यायिक अकादमियों को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है: (i) यह निचली अदालत का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में उपस्थित होने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से और अलग से रखे।भौतिक परिस्थिति का अर्थ है ए के आधार पर परिस्थिति या सामग्री। जिनमें से अभियोजन पक्ष अपनी दोषसिद्धि की मांग कर रहा है; (ii) खंड 313 के तहत अभियुक्त की जांच का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके खिलाफ पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाना है; (iii) न्यायालय को आम तौर पर उन भौतिक परिस्थितियों से बचना चाहिए जो विशेष अभियुक्त के मामले पर विचार करते समय अभियुक्त को विचार से नहीं रोकती हैं; (iv) अभियुक्त के सामने भौतिक परिस्थितियों को रखने में विफलता एक गंभीर अनियमितता है।यह मुकदमे को दूषित कर देगा यदि यह दिखाया जाता है कि उसने आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह दिखाया है; (v) यदि

आरोपी के सामने भौतिक परिस्थिति रखने में किसी भी अनियमितता के परिणामस्वरूप न्यायाधीश की विफलता नहीं होती है, तो यह एक उपचार योग्य दोष बन जाता है। हालांकि, यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, एक विचार घटना की तारीख से समय बीतने पर होगा; (vi) यदि ऐसी अनियमितता ठीक की जा सकती है, तो अपील न्यायालय भी आरोपी से उस भौतिक परिस्थिति पर सवाल कर सकती है जो उसके सामने नहीं रखी गई है; और (vii) किसी मामले में, मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के तहत संबंधित आरोपी का पूरक बयान दर्ज करने के चरण से निचली अदालत में भेजा जा सकता है। (viii) इस प्रश्न का निर्णय करते समय कि क्या चूक के कारण अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, विवाद उठाने में देरी उन कई कारकों में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 16] [767-डी-जी; 768-ए-सी]

तारा सिंह बनाम राज्य 1951 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 49; शिवाजी सहबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एससीसी 793 : [1974] 1 एससीआर 489; एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1976) 2 एस.सी.सी 819; सैमसुल हक बनाम असम राज्य (2019) 18 एस.सी.सी. 161 - पर निर्भर था।

2.1 वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई एकमात्र परिस्थिति पीडब्लू5 के साक्ष्य में है, जिसने कहा कि अपीलकर्ता अपने हाथ में एक कट्टा लिए गैलरी के द्वार के पास बाहर खड़ा था। उसे किसी भी स्पष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के तहत अपीलकर्ता का एक

लंबा बयान है जिसमें अपीलकर्ता से 42 प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न सं. 13 पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा अपदस्थ किए जाने के बारे में है। मान लीजिए, यह अपीलकर्ता के सामने नहीं रखा गया था कि यह अभिलेख पर लाया गया है कि वह गैलरी के द्वार के पास हाथ में एक कट्टा लेकर बाहर खड़ा था। यह सच है कि उनके द्वारा हर सवाल का जवाब दिया गया है "मुझे नहीं पता। जानते हैं"। यदि दंड प्रक्रिया संहिता की रि.या.(सि.) खंड 313 के तहत अपीलकर्ता के बयान में दी गई सभी परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है, तो सामान्य खुफिया जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह आभास होगा कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। यही कारण है कि कोई भी अपीलकर्ता को दोष नहीं दे सकता जब उसने हर प्रश्न का मानक उत्तर दिया क्योंकि उसके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं रखा गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा लिखित प्रस्तुतियों के पैराग्राफ 13 में, एक विशिष्ट तर्क उठाया गया था कि अपीलकर्ता के खिलाफ पेश होने वाली एकमात्र परिस्थिति को दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के तहत बयान में नहीं रखा गया था। यह विवाद में नहीं है कि तर्क के इस हिस्से पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाता है। निचली अदालत ने आरोपी की ओर से पेश वकील द्वारा की गई दलीलों को फिर से पेश नहीं किया है। [पैरा 10] [760-एफ-एच; 761-ए-बी]

2.2 अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपीलकर्ता के खिलाफ दिखाई देने वाली एकमात्र कथित दोषपूर्ण परिस्थिति को दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के तहत उसके बयान में नहीं रखा गया है और इसलिए, उसे उक्त परिस्थिति को समझाने का कोई अवसर नहीं मिला है। इसके अलावा, उसका दोषसिद्धि केवल इसी परिस्थिति पर आधारित है। [पैरा 11] [761-सी]

2.3 केवल उस परिसर के बाहर एक हथियार के साथ अपीलकर्ता की उपस्थिति के संबंध में पीडब्लू5 के संस्करण के आधार पर, जहाँ अपराध हुआ था, अपीलकर्ता की संलिप्तता को साबित किया गया है। उसके खिलाफ कोई अन्य सबूत आत्यन्तिक रूप नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपीलकर्ता के खिलाफ कई आपत्तिजनक परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ साक्ष्य में केवल एक ही परिस्थिति दिखाई देती है। अभियोजन पक्ष ने 37 गवाहों से पूछताछ की। अपीलकर्ता के खिलाफ सामग्री पी. डब्ल्यू. 5 के साक्ष्य में एक वाक्य के रूप में है। अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की रि.या.(सि.) धारा 313 के तहत उसकी जाँच के दौरान उसके खिलाफ अभियोजन खंड के एकमात्र आरोप के साथ सामना नहीं किया गया था। अपीलकर्ता के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया था। यह घटना 1995 की है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस पहलू पर निचली अदालत के समक्ष तर्क दिया गया था क्योंकि निचली अदालत ने अपीलकर्ता के वकील की दलीलों को पुनः प्रस्तुत नहीं किया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष, इसका निश्चित रूप से प्रचार किया गया था क्योंकि यह लिखित प्रस्तुतियों का एक हिस्सा है। यहाँ तक कि यह मानते हुए भी कि दोष या अनियमितता ठीक की जा सकती थी, सवाल यह है कि क्या आज अपीलार्थी-अभियुक्त को उक्त परिस्थिति की व्याख्या करने के लिए बुलाया जा सकता है। घटना के 27 साल से अधिक समय बीत चुका है। समय बीतने पर विचार करते हुए, अब इस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता की रि.या.(सि.) खंड 313 के तहत अपीलकर्ता का आगे का बयान दर्ज करने के लिए मामले को निचली अदालत को भेजना अन्यायपूर्ण होगा। मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ता को 27 साल पहले हुई किसी बात का जवाब

देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अपीलकर्ता पहले ही 10 वर्ष और 4 महीने की अवधि के लिए कारावास से गुजर चुका है। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि दूषित हो जाती है। मामले के तथ्यों में रिमांड का विकल्प अनुचित होगा। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को भी दरकिनार कर दिया गया है। [पारस 18-20,23] [769-सी-एच; 770-ए-बी; 771-बी]

वाहिता बनाम तमिलनाडु राज्य 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी 174 - प्रतिष्ठित।

रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य (2009) 6 एस.सी.सी. 595: [2009] 7 एस.सी.आर 653; सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 10 एस.सी.सी 270 : [2014] 10 एस.सी.आर 608; महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य (2020) 10 एस.सी.सी 108; सत्यवीर सिंह राठी अन्य सहायक पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा से राज्य (2011) 6 एस.सी.सी 1 : [2011] 6 एस.सी.आर. 138 - संदर्भित।

निर्णयज विधि संदर्भ

[2009] 7 एससीआर 653 में अनुच्छेद 5 संदर्भित है

[2014] 10 एससीआर 608 में अनुच्छेद 5 संदर्भित है

[2011] 6 एससीआर 138 में अनुच्छेद 6 संदर्भित है

[1974] 1 एससीआर 489 में 12 पर भरोसा किया है

आपराधिक अपील अधिकार क्षेत्र दाण्डिक अपीलीय सं.
1471/2023 |

सी.आर.एल.ए. सं. 32/2004 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.11.2018 के निर्णय और आदेश से।

सुमित वर्मा, सुमित कुमार, महिंदर प्रताप सिंह, विनय कुमार, अधिवक्तागण। अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता, चिराग एम. श्रॉफ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्या., अभय एस. ओका,

1. अनुमति प्रदान की गई।

तथ्यात्मक पहलू

2. अपीलकर्ता (अभियुक्त संख्या 2) को सत्र न्यायालय द्वारा 27 अगस्त 2003 के फैसले द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था (संक्षेप में, 'भा.दं.सं.'). धारा 302 के तहत अपराध के लिए, अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे आईपीसी की धारा 307 और धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था। जिसके लिए उन्हें 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

3. एक विमल (मृतक होने के बाद से) और पांच अन्य लोगों के साथ इस आरोपी के खिलाफ आरोप था कि 1 अक्टूबर 1995 को लगभग 3:30 बजे, उन्होंने जवाहर लाल (अ.सा. 3) और उनके रिश्तेदारों को आपराधिक रूप से डराने-धमकाने और उनकी हत्या

करने की साजिश रची। आरोप यह है कि अ.सा. -3 अपना स्वयं का केबल टीवी नेटवर्क चला रहा था, और आरोपी चाहता था कि वह उक्त केबल टीवी नेटवर्क को बंद कर दे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि 1 अक्टूबर 1995 को लगभग 3:30 बजे, आरोपी पी. डब्ल्यू. 3 जवाहर लाल के घर में घुस गया, जहाँ वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रहा था। आरोपी नंबर 4 और 5 ने ओमी देवी पर अपनी रिवॉल्वर से गोलियां चलाईं, पीडब्ल्यू 3 की मां और चंद्र शेखर (मृतक - पीडब्ल्यू 3 का भाई)। आरोपी नंबर 3 और मृतक विमल ने चंद्र शेखर (मृतक) और ओमी पर खंजर और चाकू से हमला किया। पीडब्ल्यू 3 और पीडब्ल्यू 7 को गंभीर चोटें आईं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चंद्र शेखर की मृत्यु हो गई। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि वर्तमान अपीलकर्ता (अभियुक्त संख्या 2) के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि जब 6 अन्य आरोपी अ.सा.-3 के घर में घुसे, तो अपीलकर्ता अपने हाथ में कट्टा (देशी बंदूक) लेकर गैलरी के गेट के पास खड़ा था। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

प्रस्तुतियाँ

4. अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने बताया कि केवल पीडब्ल्यू 5 वेद प्रकाश ने बयान दिया कि अपीलकर्ता हाथ में कट्टा लिए गैलरी के गेट के पास खड़ा था। हालांकि, पीडब्ल्यू 3 ने जिरह में स्वीकार किया कि उसने घटना के दिन मौजूदा अपीलकर्ता को नहीं देखा था और उसका नाम पीडब्ल्यू 5 ने उसे बताया था। वकील ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 84 में यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि पीडब्ल्यू 13 ने भी अपीलकर्ता को देखा था, वास्तव में,

पीडब्ल्यू 13 ने अपीलकर्ता के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

5. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली एकमात्र परिस्थिति कि वह एक कट्टा के साथ गैलरी के गेट के बाहर खड़ा था, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सीआरपीसी') की धारा 313 के तहत उनके बयान में नहीं रखी गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तर्क का विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचार किया गया था, जो अपीलार्थियों की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों में जगह पाता है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने मामले **रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य 1; सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य; महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य 3; और समसुल हक बनाम असम राज्य** में न्यायालय का अवलंब किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ अपनी परीक्षा के दौरान एकमात्र परिस्थिति को रखने में निचली अदालत की विफलता के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीश की विफलता हुई है।

6. प्रतिवादी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने प्रतिपरिक्षण अ.सा.-5 नहीं किया था। उन्होंने **सत्यवीर सिंह राठी सहायक पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो राज्य द्वारा.** के मामले में इस अदालत के एक फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के तहत बयान दर्ज करने में चूक या दोष के बारे में आपत्ति जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए ताकि दोष को ठीक किया जा सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त

तर्क निचली अदालत द्वारा निर्णय पारित किए जाने के 16 साल बाद उठाया गया था। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि इस स्तर पर, इस आपत्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि उक्त आपत्ति पहले किसी भी समय नहीं उठाई गई थी, यह दर्शाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र परिस्थिति रखने में अदालत की विफलता के कारण अपीलकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

हमारा विचार

7. हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह था कि छह अभियुक्तों ने याचिका दायर की थी। अ.सा._3 के सदन पर, अपीलकर्ता हाथ में एक कट्टा लिए बाहर खड़ा था। विवादित फैसले के पैराग्राफ 84 में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपीलकर्ता के संबंध में अ.सा. 3 का साक्ष्य कुछ संदेह पैदा करता है। हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पी. डब्ल्यू. 5 और पी. डब्ल्यू. 13 के साक्ष्य उनकी भागीदारी के संबंध में स्पष्ट और सुसंगत हैं। इसलिए हमने अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों के साक्ष्य का अध्ययन किया है। अ.सा. 3 जवाहर लाल ने लगभग 3 बजे अपने घर में 6 अन्य अभियुक्तों के प्रवेश के बारे में गवाही दी अक्टूबर 1995 को 3:30 बजे। उन्होंने यह बयान नहीं दिया कि अपीलकर्ता हाथ में कट्टा लिए बाहर खड़ा था। आगे की जाँच में, उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में, उन्होंने गलत तरीके से उल्लेख किया है कि आरोपी राजिंदर कुमार घटनास्थल की रखवाली कर रहा था। उन्होंने कहा कि यह अपीलकर्ता था जो घटनास्थल की रखवाली कर रहा था। उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता अ.सा. -3 के संस्करण के संबंध

में संदेह व्यक्त किया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण यह है कि अ.सा. -3 ने यह भी कहा कि घटना के दिन उसने अपीलकर्ता को नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम अ.सा. 5 वेद प्रकाश ने उसे बताया था। इसलिए, अपीलकर्ता को फंसाने के लिए अ.सा. 3 की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

8. हमने अ.सा.-13 के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। यद्यपि उच्च न्यायालय ने प्रेक्षित किया है कि अ.सा.-13 ने अपीलकर्ता को हाथ में कट्टा लिए बाहर खड़े होने की भूमिका सौंपी है, लेकिन हम पाते हैं कि अ.सा. 13 ने अपने साक्ष्य में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।

9. इस प्रकार, जो बचा है वह अ.सा. 5 के साक्ष्य हैं। उन्होंने अपनी मुख्य-जाँच में केवल इतना ही कहा कि उन्होंने राज कुमार को गैलरी के द्वार पर हाथ में कट्टा लिए खड़ा देखा। उन्होंने अदालत में अपीलकर्ता की पहचान की।

10. अतः, वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध अ.सा. 5 के साक्ष्यों में रिकॉर्ड में लाई गई एकमात्र परिस्थिति इस प्रकार है - जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता गैलरी के द्वार के बाहर हाथ में एक कट्टा लेकर खड़ा था। उसे किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के तहत अपीलकर्ता का एक लंबा बयान है जिसमें अपीलकर्ता से 42 प्रश्न पूछे गए थे। प्र.सं-13 पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा अपदस्थ किए जाने के बारे में है। मान लीजिए, यह बात अपीलार्थी के सामने नहीं रखा गया था कि यह अभिलेख पर मौजूद है कि वह गैलरी के द्वार के पास बाहर हाथ में एक कट्टा लेकर खड़ा था। यह सच है कि उनके द्वारा दिया गया हर सवाल का जवाब है "मुझे नहीं पता"। यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता

के बयान में दी गई सभी परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है, तो सामान्य खुफिया जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह आभास होगा कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। यही कारण है कि कोई भी अपीलकर्ता को दोष नहीं दे सकता है जब उसने प्रत्येक प्रश्न के मानक उत्तर दिए क्योंकि कुछ भी प्रतिकूल नहीं था। जो उनके खिलाफ रखा गया था। हम यहां ध्यान दें सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा लिखित प्रस्तुतियों के पैराग्राफ 13 में, एक विशिष्ट तर्क उठाया गया था कि अपीलकर्ता के खिलाफ पेश होने वाली एकमात्र परिस्थिति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभिकथन में नहीं रखा गया था। यह विवाद में नहीं है कि तर्क के इस हिस्से पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाता है। हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि निचली अदालत ने अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों को पुनः प्रस्तुत नहीं किया है।

11. इस प्रकार, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपीलकर्ता के खिलाफ दिखाई देने वाली एकमात्र कथित आपत्तिजनक परिस्थिति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसके बयान में नहीं रखा गया है और इसलिए, उसे उक्त परिस्थिति को समझाने का कोई अवसर नहीं मिला है। इसके अलावा, उसकी सजा केवल इसी परिस्थिति पर आधारित है।

12. इसलिए, हमें निचली अदालत की ओर से उपरोक्त चूक के प्रभाव पर विचार करना होगा। इस पहलू पर कानून अब पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निर्णयों पर निर्भर नहीं है, इस पहलू पर अन्य महत्वपूर्ण निर्णय हैं। पहला प्रासंगिक निर्णय *तारा सिंह बनाम राज्य*⁶ के मामले में इस

न्यायालय के चार माननीय न्यायाधीशों की पीठ का है। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (संक्षेप में, '1898 की दंड प्रक्रिया संहिता') की खंड 342 के प्रावधान पर विचार किया। सी. आर. पी. सी. की खंड 313 और 1898 की सी. आर. पी. सी. की खंड 342 पर सामग्री पैराग्राफ 18 में हैं, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"18. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एक अभियुक्त की धारा 342 के तहत ठीक से जाँच की जानी चाहिए और जैसा कि प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप्स ने संकेत दिया है। द्वारकानाथ में वर्मा बनाम सम्राट [द्वारकानाथ] वर्मा बनाम सम्राट, ए.आई.आर. 1933 पी.सी. 124 पी.130:1933 एस.सी.सी. ऑनलाइन पी.सी. 11], यदि साक्ष्य में एक बिंदु को अभियुक्त के खिलाफ महत्वपूर्ण माना जाता है और दोषसिद्धि का उद्देश्य इसके आधार पर होना है, तो यह सही और उचित है कि आरोपी से मामले के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए और उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर वह चाहता है तो। यह एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य प्रावधान है और मैं इसे अनदेखा करने की अनुमति नहीं दे सकता इससे पता चलता है कि कई मामलों में इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से सत्र न्यायालयों में। लेकिन चाहे मामला सत्र न्यायालय में उत्पन्न हो या कमिटिंग मजिस्ट्रेट के मामले में, यह महत्वपूर्ण है कि धारा 342 के प्रावधानों का निष्पक्ष और ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

फिर से पैराग्राफ 23 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"23. धारा 342 अभियुक्त से "उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने" के उद्देश्य से पूछताछ करने की अपेक्षा करती है। अब यह स्पष्ट है कि जब सत्र न्यायालय को इस धारा के तहत परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, तो निर्दिष्ट साक्ष्य सत्र न्यायालय में साक्ष्य और वे परिस्थितियाँ हैं जो उस न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ उपस्थित होती हैं। इसलिए कमिटिंग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रखे गए प्रश्नों और उत्तरों को पढ़ना और अभियुक्त से पूछना पर्याप्त नहीं है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ कहना है। वर्तमान मामले में ऐसा भी नहीं था। अपीलकर्ता से उनके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन उनसे पूछा गया था कि क्या कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान और वहां दिए गए उनके जवाब सही तरीके से दर्ज किए गए थे। यह धारा की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है।"

इस पहलू पर दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है। **शिवाजी सहबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में यह एक निर्णय है। निर्णय के पैराग्राफ 16 में, इस न्यायालय ने 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 की आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के मुद्दे की जांच की। पैराग्राफ 16 इस प्रकार है:

"16. अभियुक्त द्वारा दिए गए कबूलनामे के अनुसार आपत्तिजनक सामग्री की खोज साक्ष्य की तीसरी श्रेणी का गठन करती है। जाहिर है, स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य है, लेकिन खोजें हैं, बशर्ते वे आरोपी के अपराध के लिए प्रासंगिक हों। जहां तक अभियुक्त 2 का संबंध है, उसके बयान के परिणामस्वरूप चाकू की खोज हुई (विदे पंचनामा, अनुच्छेद 13) 7 (1973) 2 एससीसी 793 कोर्समें, चाकू बहुत पहले खोजे गए थे और अब नहीं लेकिन यह चाकू दफन हो गया था और आरोपी ने अपने घर की एक दीवार के कोने में एक गड्ढे से बरामद किया था। रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार चाकू के ब्लेड पर मानव रक्त था, एमओ 5/1। दूसरे आरोपी के बयान के आधार पर उसने उसके कपड़े भी उठा लिए। घटना के दिन उसने शर्ट और पैंट पहनी थी और पीडब्ल्यू 13 , एक पड़ोसी ने कहा कि दूसरा आरोपी सोमवार को शाम लगभग 6 बजे उसके पास आया था जब हरिबा की मृत्यु हो गई थी। अपने घर पर ताला लगा हुआ था , उसे गवाहों के घर में अपने कपड़े रखने की अनुमति दी जा सकती थी। इसके बाद उसने अपने कपड़े एक खाली खोखा के नीचे छोड़ दिए, जहां से उसने खुद उन्हें बाहर निकाला जब वह बाद में पुलिस की कंपनी में आया। कपड़ों पर खून के धब्बे हैं और केमिकल एग्जामिनर द्वारा यह पाया

जाता है कि पेंट पर खून उसी ब्लड ग्रुप का है जो मृतक का है। जब दूसरे आरोपी से धारा 342 के तहत पूछा गया, रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के बारे में जब उसने शर्ट, एमओ 5/2 और चाकू के ब्लेड पर मानव रक्त के धब्बे देखे तो एमओ 5/1, उन्होंने केवल जवाब दिया, "मुझे नहीं पता"। उन्होंने कपड़े और चाकू बरामद करने के तथ्य को भी झूठा बताया। गंजे इनकार के बावजूद, हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के साथ यह विश्वास करने के इच्छुक हैं कि चाकू और शर्ट की पहचान उसके रूप में की गई है और चूंकि उसने उन्हें बरामद किया था, इस तरह पुलिस को इस तथ्य का पता चला, उक्त आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक निष्कर्ष उपलब्ध थे। हम यहां ट्रायल जज द्वारा की गई एक गंभीर चूक देख सकते हैं और किसी भी अदालत द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरे आरोपी द्वारा हमले के समय कथित तौर पर पहनी गई पेंट में मृतकों के समूह से संबंधित खून के धब्बे हैं। यह परिस्थिति उसे अपराध से थोड़ा स्पष्ट रूप से बांधती है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परिस्थिति के बारे में अदालत द्वारा उससे कोई विशेष सवाल नहीं किया गया है। यह कठोर कानून है, फिर भी मौलिक है, कि कैदी का ध्यान हर उत्तेजक सामग्री पर आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि वह इसे समझाने में सक्षम हो सके। यह आपराधिक मुकदमे की बुनियादी

निष्पक्षता है और इस क्षेत्र में विफलताएं मुकदमे की वैधता को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकती हैं, अगर परिणामस्वरूप न्याय का उल्लंघन होता है। हालांकि, जहां इस तरह की घटना हुई है, यह वास्तव में कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है और इस तरह के दोष के कारण पूर्वाग्रह अभियुक्त द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। अभियुक्त के समक्ष साक्ष्य सामग्री प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में, न्यायालय को आमतौर पर ऐसी सामग्री को विचार से रोकना चाहिए। अपीलीय अदालत के लिए यह भी खुला है कि वह आरोपी के वकील को यह दिखाने के लिए बुलाए कि आरोपी के पास उसके खिलाफ स्थापित परिस्थितियों के संबंध में क्या स्पष्टीकरण है, लेकिन उसे नहीं दिया गया है और यदि आरोपी जवाब देने में असमर्थ है। अपीलीय अदालत ऐसी परिस्थितियों का कोई भी प्रशंसनीय या उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकती है, अदालत यह मान सकती है कि कोई स्वीकार्य उत्तर मौजूद नहीं है और यहां तक कि अगर आरोपी से ट्रायल कोर्ट में उचित समय पर पूछताछ की गई थी, तो भी वह प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होगा। उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं है, जिन पर ट्रायल कोर्ट ने अपनी दोषसिद्धि के लिए भरोसा किया था। ऐसे मामले में, न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड

342 के अनुपालन के संबंध में एक गंभीर अनियमितता हुई है, लेकिन यह नहीं दिखाया गया है कि चूक से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने, न ही निचली अदालत ने मृतक के रक्त समूह की पैंट पर रक्त की उपस्थिति पर भरोसा नहीं किया है। हमें यह नहीं दिखाया गया है कि आरोपी इस रासायनिक खोज के लिए क्या स्पष्टीकरण दे सकता था, विशेष रूप से जब हमें याद हो कि चाकू के ब्लेड पर मानव रक्त के बारे में सवाल का उसका जवाब था "मुझे नहीं पता"। अपीलार्थियों के वकील कोई बुद्धिमान स्पष्टीकरण नहीं दे सके और "रक्त" गवाही अपराध को अभियुक्त के करीब ले जाती है। हालाँकि, हम इस साक्ष्यपूर्ण परिस्थिति पर बहुत अधिक भरोसा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, हालाँकि हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि निचली निचली अदालत की इस लापरवाही के कारण क्या हुआ था। पर एक प्रासंगिक तथ्य का तर्क दिया जा रहा है जो अभियोजन पक्ष के लिए अनुपलब्ध है। सत्र न्यायाधीशों से बहुत सावधानी की अपेक्षा की जाती है जो गंभीर मामलों की सुनवाई करते हैं और प्रत्येक दोषपूर्ण परिस्थिति को इकट्ठा करते हैं और इसे अभियुक्त के सामने रखते हैं, भले ही एक लंबे मुकदमे के अंत में न्यायाधीश थोड़ा परेशान हो सकता है।"

(जोर दिया गया)

13. फिर हम इस न्यायालय के निर्णय पर आते हैं एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) का मामला पैराग्राफ 22 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"22. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 न्यायालय का कर्तव्य है कि वह किसी भी जांच या मुकदमे में आरोपी से सवाल पूछे ताकि वह अपने खिलाफ़ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट कर सके। यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में इस प्रकार है कि अभियुक्त के खिलाफ़ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से उसके सामने रखा जाना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता के बराबर है जो मुकदमे को दूषित करती है यदि यह दिखाया जाता है कि इसने आरोपी को पूर्वाग्रहित किया है। यदि अनियमितता, वास्तव में, न्यायाधीश की विफलता का कारण नहीं बनती है, तो संहिता की धारा 537 के तहत इसका इलाज किया जा सकता है।"

(जोर दिया गया)

14. फिर हम समसुल हक के मामले में एक निर्णय पर आते हैं जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था। पैराग्राफ 21 से 23 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"21. हमारे विचार में सबसे महत्वपूर्ण पहलू, और जो अभियोजन पक्ष के मामले में ताबूत में कील ठोकने वाला तरीका वह है, जिस तरह से अदालत ने मामले को

अभियुक्त 9 के पास रखा, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान। कम से कम कहने के लिए यह लापरवाही है।

22. यह कहना ठीक नहीं है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त के सामने दोषारोपण करने वाली सामग्री रखी जानी चाहिए ताकि अभियुक्त को अपना बचाव करने का उचित मौका मिल सके। यह ऑडी अल्टरम पार्टम सिद्धांतों की मान्यता में है। इसके अलावा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित निर्णय, हम उपयोगी रूप से इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं

असरफ अली बनाम असम राज्य में [असरफ] अली बनाम असम राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 328: (2010) 4 एस. सी. सी. (सीआरआई) 278] निम्नलिखित पैराग्राफ में हैं: (एस. सी. सी. पी.334, पैरा 21-22)

21. "संहिता की धारा 313 अदालत को यह कार्य सौंपती है कि वह आरोपी को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पूछताछ या परीक्षण प्रश्न पूछे। यह आवश्यक परिणाम के रूप में इस प्रकार है कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से उसके सामने रखा जाना आवश्यक है और ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता के समान है जो मुकदमे को दूषित करती है, यदि यह दिखाया जाता है कि अभियुक्त पूर्वाग्रह से ग्रस्त था।

22. संहिता की खंड 313 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यदि साक्ष्य में अभियुक्त के खिलाफ एक बिंदु महत्वपूर्ण है, और दोषसिद्धि उसी पर आधारित होना है, तो यह सही और उचित है कि अभियुक्त से मामले के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए और उसे समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए। जहां विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में एक दोषारोपण सामग्री पर कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया है, वह मुकदमे को दूषित करता है। बेशक, ये सभी इस बात पर निर्भर हैं कि क्या वे न्यायाधीश की विफलता या पूर्वाग्रह का कारण बने हैं। इस न्यायालय ने भी एस हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1976) 2 एस. सी. सी. 819:1976 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 324] दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 342 (संहिता की धारा 313 के अनुरूप) में इसी तरह का विचार व्यक्त किया। पर विचार करते हुए। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के लिए अपने प्रासंगिक पहलुओं में दोषारोपण सामग्री का गैर-संकेत अभियोजन मामले की भेद्यता को बढ़ाता है। धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करना एक उद्देश्यहीन अभ्यास नहीं है।"

23. उपरोक्त टिप्पणियां करते समय, इस न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों के अपने पहले के फैसले का भी उल्लेख किया शिवाजी साहबराव बोबडे पीठ महाराष्ट्र राज्य (शिवाजी साहबराव बोबडे पीठ महाराष्ट्र राज्य) महाराष्ट्र (1973) 2 एस. सी. सी. 793:1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.)

1033], जिसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अभियुक्त के खिलाफ उपस्थित होने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर प्रश्न रखने की चूक के परिणाम पर विचार किया, और यह आवश्यकता कि अभियुक्त का ध्यान प्रत्येक दोषारोपण सामग्री की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि वह स्पष्टीकरण दे सके। आम तौर पर, ऐसी स्थिति में, ऐसी सामग्री जो अभियुक्त के सामने नहीं रखी जाती है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के तहत एक निष्पक्ष जांच होती है, मामला निचली निचली अदालत को भेजे जाने में सक्षम है, जिसमें उस चरण से फिर से प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है जिस पर अभियोजन पक्ष को बंद किया गया था [शिवाजी] सहबराव बोबडे बनाम राज्य महाराष्ट्र (1973) 2 एस. सी. सी. 793:1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1033]"

(जोर दिया गया)

15. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने भी **वाहिता बनाम तमिलनाडु राज्य** मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर अवलंब किया। यह मामला सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ करते समय की गई चूक के परिणामों के निपटारन से संबंधित नहीं है। यह केवल एक आकस्मिकता से संबंधित है जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को चुनौती नहीं दी जाती है। अब हम सत्यवीर सिंह के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर आते हैं, जिस पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था। निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया

है कि अपील में पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का पालन न करने के आधार पर दोषसिद्धि की चुनौती पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि आरोपी यह प्रदर्शित नहीं करता कि उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया है। यदि जल्द से जल्द कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो संबंधित अभियुक्त का एक अतिरिक्त बयान दर्ज करके दोष को ठीक किया जा सकता है। उक्त निर्णय का निष्कर्ष और सार यह है कि इतनी लंबी देरी यह तय करने में एक कारक हो सकती है कि जाँच विकृत है या नहीं। इसके अलावा, **शिवाजी साहबराव बोबडे के मामले में** जो बाध्यकारी है वह बड़ी पीठ का निर्णय है, जो यह निर्धारित करता है कि यदि अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीश की विफलता होती है, तो मुकदमा दूषित हो जाएगा।

16. इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

- (i) ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से और अलग-अलग रखे। भौतिक परिस्थिति का अर्थ है वह परिस्थिति या सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष उसकी दोषसिद्धि की मांग कर रहा है;
- (ii) धारा 313 के तहत अभियुक्त की जाँच का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके खिलाफ पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाना है।

- (iii) न्यायालय को आम तौर पर उन भौतिक परिस्थितियों से बचना चाहिए जो विशेष अभियुक्त के मामले से निपटने के दौरान आरोपी पर विचार नहीं की जाती है।
- (iv) यदि यह दिखाया जाता है कि उसने अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह दिखाया है तो यह मुकदमे को दूषित कर देगा।
- (v) यदि अभियुक्त के सामने भौतिक परिस्थिति रखने में किसी भी अनियमितता के परिणामस्वरूप न्यायाधीश की विफलता नहीं होती है, तो यह एक उपचार योग्य दोष बन जाता है। हालांकि, यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, एक घटना की तारीख से समय के बीतने पर होगा।
- (vi) यदि ऐसी अनियमितता ठीक की जा सकती है, तो अपील न्यायालय भी अभियुक्त से उस भौतिक परिस्थिति पर सवाल कर सकता है जो उसके सामने नहीं रखी गई है; और
- (vii) किसी दिए गए मामले में, मामले को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत संबंधित अभियुक्त के पूरक बयान दर्ज करने के चरण से ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सकता है।
- (viii) इस प्रश्न का निर्णय करते समय कि क्या चूक के कारण अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, विवादित मुद्दा उठाने में देरी उन कई कारकों में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

17. अब, हमें इस मामले के तथ्यों पर इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करना होगा। उच्च न्यायालय ने

अभियुक्त के खिलाफ 4 जुलाई 1998 को बनाए गए आरोप को दोहराया है, जो इस प्रकार है:

"चार्ज करें

6. निचली अदालत द्वारा 4 जुलाई 1998 के आदेश द्वारा सभी अभियुक्तों के खिलाफ बनाया गया आरोप इस प्रकार था:

- (i) कि 1 अक्टूबर 1995 को या उससे पहले दिल्ली में दोपहर लगभग 3.30 बजे ए1 से ए6 विमल (अब मृत) के साथ पीडब्ल्यू 3 की विफलता के कारण जवाहर लाल (पीडब्ल्यू 3) और उनके रिश्तेदारों की हत्या को आपराधिक रूप से डराने और अंजाम देने के लिए सहमत हुए। पश्चिमपुरी के क्षेत्र में अपने टीवी केबल नेटवर्क को रोकने के लिए धारा 120 बीआईपीसी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश का अपराध करना।
- (ii) 1 अक्टूबर 1995 को पश्चिमपुरी के मकान नम्बर. 618/3 में, उपरोक्त साजिश के अनुसरण में, ए-4 और ए-5 ने अपनी-अपनी रिवॉल्वर से श्रीमती ओमी देवी और चंदर शेखर पर गोलियां चलाईं। जबकि विमल और ए-3 ने चंदर शेखर और ओमी पर अपने-अपने खंजर और चाकू से हमला किया और उनकी हत्या कर दी और इस प्रकार उन सभी ने भा.दं.सं. की धारा 302 120ख के साथ सहपठित दंडनीय अपराध किया था।

(iii) उन सभी ने आपराधिक साजिश के तहत अ.सा. 3 और अ.सा. 7 दोनों पर अपनी रिवाल्वर से गोलियां चलाकर अ.सा. 3 की हत्या करने का प्रयास किया। जिसके कारण उन दोनों को खतरनाक चोटें आईं और इस तरह उन सभी ने भा.दं.सं की धारा 307 के साथ 120ख के तहत दंडनीय अपराध किया।

(जोर दिया गया)

18. उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 7 में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अपीलकर्ता को छोड़कर सभी अभियुक्तों के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 452 के तहत एक अलग आरोप तैयार किया गया था जिसे 120-बी के साथ सहपठित था। इस प्रकार, अपीलकर्ता के खिलाफ बनाया गया आरोप आपराधिक षड़यंत्र में एक पक्ष होने का था। यह भी आरोप है कि सभी अभियुक्तों ने अपनी रिवाल्वर से गोलियां चलाईं। केवल उस परिसर के बाहर एक हथियार के साथ अपीलकर्ता की उपस्थिति के संबंध में अ.सा. 5 के संस्करण के आधार पर, जहाँ अपराध हुआ था, अपीलकर्ता की संलिप्तता को साबित किया गया है। उसके खिलाफ कोई अन्य सबूत आत्यन्तिक रूप से नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ साक्ष्य में केवल एक ही परिस्थिति दिखाई देती है। अभियोजन पक्ष ने जांच की 37 गवाहों में अपीलकर्ता के खिलाफ सामग्री पी. डब्ल्यू. 5 के साक्ष्य में एक वाक्य के रूप में है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यदि हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के बयान में

पूछे गए 42 प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो सामान्य बुद्धि रखने वाले किसी भी आरोपी को यह आभास होगा कि उसके खिलाफ बिल्कुल कोई सामग्री नहीं है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी जांच के दौरान अपीलकर्ता का सामना उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष के एकमात्र आरोप के साथ नहीं किया गया था। इस तरह, तथ्यों पर, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के लिए एक गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न किया गया था।

19. यह घटना 1995 की है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस पहलू पर निचली अदालत के समक्ष तर्क दिया गया था क्योंकि निचली अदालत ने अपीलकर्ता के वकील की दलीलों को पुनः प्रस्तुत नहीं किया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष, इसका निश्चित रूप से प्रचार किया गया था क्योंकि यह लिखित प्रस्तुतियों का एक हिस्सा है।

20. यह मानते हुए भी कि दोष या अनियमितता ठीक की जा सकती थी, सवाल यह है कि क्या आज, अपीलार्थी-अभियुक्त को उक्त परिस्थिति की व्याख्या करने के लिए बुलाया जा सकता है। घटना को 27 साल से अधिक समय बीत चुका है। समय के बीतने पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि अब इस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का आगे का बयान दर्ज करने के लिए मामले को निचली न्यायालय को भेजना अन्यायपूर्ण होगा। मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ता को 27 साल पहले हुई किसी बात का जवाब देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इस मामले का एक और पहलू है जिसने हमें रिमांड का आदेश पारित नहीं करने के लिए राजी किया। कथित कारण यह है कि

अपीलकर्ता पहले ही 10 वर्ष और 4 महीने की अवधि के लिए कारावास से गुजर चुका है।

21. इस निर्णय को देने से पहले, हमें धारा 313 में जोड़ी गई उप-धारा (5) पर ध्यान देना चाहिए। सी.आर.पी.सी डब्ल्यू.ई.एफ. 31 दिसंबर 2009 के उप-धारा (5) इस प्रकार है:

"313. अभियुक्त की जाँच करने की शक्ति। (1)...

(2)....

(3)...

(4)...

(5) न्यायालय प्रासंगिक प्रश्न तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की मदद ले सकता है जिन्हें अभियुक्त के समक्ष रखा जाना है और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।"

कई आपराधिक मुकदमों में, बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की जाती है, और सबूत बहुत बड़े होते हैं। यह सच है कि न्यायिक अधिकारियों को धारा 313 के महत्व को समझना होगा। लेकिन अब न्यायालय को प्रासंगिक प्रश्न तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की मदद लेने का अधिकार है। इसलिए, जब विचारण न्यायाधीश अभियुक्त से सवाल पूछने से पहले धारा 313 के तहत अभियुक्त से सवाल पूछने के लिए तैयार करता है, तो न्यायाधीश हमेशा कर सकता है। विद्वान लोक अभियोजक के साथ-साथ विद्वान बचाव वकील को उक्त प्रश्नों की प्रतियां प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए

उनकी सहायता ले सकते हैं कि आरोपी के खिलाफ दिखाई देने वाली हर प्रासंगिक सामग्री परिस्थिति उसके सामने रखी जाए। जब न्यायाधीश अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की सहायता मांगता है, वकीलों को अदालत के अधिकारियों के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि ग्राहकों के मुखपत्र के रूप में। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करते समय अभियोजन पक्ष के गवाहों की बड़ी संख्या में, न्यायिक अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 313 की उपधारा (5) का लाभ उठाने की सलाह दी जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि त्रुटियों और चूक करने की संभावना कम से कम हो।

22. 1951 में, **तारा सिंह** के मामले में फैसला सुनाते समय, इस अदालत ने अफसोस जताया कि कई मामलों में, 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के हितकारी प्रावधान पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हम हैं। हमें यह जानकर खेद है कि 72 वर्षों के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है क्योंकि हम बड़ी संख्या में मामलों में इस तरह की चूक देखते हैं। राष्ट्रीय और राज्य न्यायिक अकादमियों को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

23. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि विकृत है। मामले के तथ्यों में रिमांड का विकल्प अनुचित होगा। तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा पारित 27 अगस्त 2003 के निर्णय और आदेश के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं। 2000 के सत्र मामले संख्या 9 में, उच्च

न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को भी रद्द कर दिया गया है । हम यह स्पष्ट करते हैं कि दोनों निर्णयों को केवल तभी तक रद्द किया जाता है जब तक अपीलकर्ता का संबंध है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी अपीलकर्ता को तुरंत मुक्त कर दे जब तक कि उसे किसी अन्य मामले के संबंध में हिरासत में रखने की आवश्यकता न हो।

दिव्या पांडे

अपील स्वीकार की गई।

(सहायता: राउल सावंत और शेवाली मोंगा, एल.सी.आर.ए एस)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*